



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256244
CG-DL-E-09082024-256244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3080]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/श्रावण 18, 1946

No. 3080]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

का.आ. 3234(अ).— यतः, मै. नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य में सर्वे नंबर 128/2/ए राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-I, हीनजेवाडी, तालुका मुलाशी, पुणे जिला में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ के लिए एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 1216(अ) दिनांक 14.03.2018	3.4659	-	3.4659
2.	का.आ. 4451(अ) दिनांक 09.12.2019	1.6596	-	5.1255
3.	का.आ. 5312(अ) दिनांक 15.11.2022	-	0.0655	5.0600

और यतः, मै. नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 1.11 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उनके पत्र नंबर एसईजेड-2024/सीआर-56/आईएनडी-2 दिनांक 18 जून, 2024 के पत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, ऐसे भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः विकास आयुक्त, सीप्स विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.11 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.11 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 3.95 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हीनजेवाड़ी	128/2/ए	1.11
कुल			1.11
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			3.95

[फा. सं. एफ. 1/14/2017-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2024

S.O. 3234(E).—Whereas, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Survey No. 128/2/A Near Rajiv Gandhi Infotech Park – Phase-I, Hinjewadi, Taluka- Mulashi, District Pune, District, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No. and Date	Notified area (in Ha)	De-notified area (in Ha)	Total resultant area (in Ha)
1.	S.O.1216(E) dated 14.03.2018	3.4659	-	3.4659
2.	S.O.4451(E)dated 09.12.2019	1.6596	-	5.1255
3.	S.O.5312(E)dated 15.11.2022	-	0.0655	5.0600

AND, WHEREAS, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd. has now proposed for de-notification of 1.11 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2024/CR-56/Ind-2 dated 18th June, 2024. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized towards the creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.11 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005, and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.11 hectares, thereby making the resultant area as 3.95 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village	Survey number	Area (in Hectares)
1.	Hinjewadi	128/2/A	1.11
Total			1.11
Grand total of the SEZ after the above deletion			3.95

[F. No. F.1/14/2017-SEZ)]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.